योजना है, यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) से (ग) उत्तर प्रदेश राज्य विधान द्वारा लखनऊ में डा० भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए अधिनियम अक्तूबर, 1989 में ही पारित कर दिया गया था । राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचनानुसार राज्य ने विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिए 244 एकड़ भूमि प्राप्त की है व निर्माण कार्य भी आरंभ हो चुका है। इस उद्देश्य के लिए राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 1990–91 में 5.00 करोड़ रु० तथा चालू वित्तीय वर्ष 1991–92 में 2.50 करोड़ रु० दिये थे। विश्व अनु० आ० विश्वविद्यालय को वित्तीय सहायता देने पर विचार केवल तभी करेगा जब विश्वविद्यालय न्यूनतम बुनियादी सुविधाएं निर्मित कर लेगा व अध्यापन तथा गैर-अध्यापन स्टाफ की प्रस्तावित न्यूनतम संख्या नियुक्त कर लेगा तथा विश्व० अनु० आयोग अधिनियम व विनियमों के प्रावधानों के अनुसार अन्य आवश्यक शर्तें पूरी कर लेगा ।

केन्द्रीय सरकार डा० अम्बेडकर के नाम पर विश्वविद्यालय स्थापित करने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है ।

India's Participation in the Reconstruction Programme in the Gulf

†*233. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the Minister of COMMERCE be pleased to state:

(a) what efforts have been made by Government to avail of the opportunities for country's participation in the reconstruction programme in the Gulf with the end of the Gulf war; and

(b) what are the areas identified to be taken up for participation for rebuilding?

†Previously Starred Question 73, transferred from 17th July, 1991.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE (SHRI P. CHIDAMBARAM): (a) Government have taken a number of steps to exploit the available opportunities in the post-war Gulf reconstruction. These steps include:--

(i) A Special Group has been set up to evolve a strategy for promotin project exports in the Gulf in the post-war situation.

(ii) A High Powered Committee with Inter-Ministerial representation has been set up to expedite Government clearance for project exports through high level Inter-Ministerial discussions.

(iii) Former Commerce Minister visited Kuwait to get first hand knowledge of the war damage in Kuwait and for talks with the concerned Kuwaiti authorities.

(iv) Overseas Construction Council of India delegation visited U.K. and U.S.A. to explore the possibilities of securing subcontracts on the contracts awarded to parties in these countries.

(v) A Composite delegation of project exporter visited Kuwait and Saudi Arabia.

(b) The areas identified for participation in the reconstruction by Indian companies include oil wells and refineries, civil construction, powerlines and alied areas and export of commodity items.

कपास के मूल्यों में वृद्धि

234. **सरदार जगजीत सिंह अरोड़ा:**
डा० जितेन्द्र कुमार जैन :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपास की कमी के कारण सितम्बर, 1990 से

मार्च, 1991 तक देश में कपास के मूल्यों में भारी वृद्धि हो गई थी ;

(ख) क्या यह भी सच है कि कपास के उपलब्ध न होने के कारण अनेक कपड़ा मिलों और हथकरघा उद्योग को गम्भीर आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है ;

(ग) यदि हां, तो इसी अवधि के दौरान देश में कपड़ा मिलों और हथकरघा उद्योग को उचित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में कपास न मिलने के क्या कारण थे ;

(घ) क्या सरकार ने देश में इन उद्योगों को आसानी से कच्चा कपास उपलब्ध कराने के लिए कोई कदम उठाये हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री अशोक गहलोत) : (क) प्रतिकूल मौसम होने तथा देश के कपास उपजाने वाले कुछ क्षेत्रों में नाशी जीव (पेस्ट) के भारी आक्रमण के फलस्वरूप कपास के उत्पादन में अप्रत्याशित गिरावट आने के कारण सितम्बर 1990 से मार्च, 1991 तक की अवधि के दौरान कपास की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है ।

(ख) वर्ष 1990–91 के कपास मौसम के दौरान कपास की मांग और पूर्ति की स्थित में उतार-चढ़ाव आने के कारण वस्त्र मिलों और हथकरघा एककों के सामने पेश आ रहे किसी भी प्रकार के गम्भीर आर्थिक संकट के बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

(ग) कपास के उत्पादन में गिरावट आने के कारण कपास की आपूर्ति स्थिति में यद्यपि कुछ कठिनाई आई और जिसके फलस्वरूप कपास की कीमतों में वृद्धि की प्रवृत्ति रही, फिर भी मौसम के दौरान मिलों को पूरी तरह से कपास उपलब्ध होती रही । इस संबंध में हथकरघा को भी किसी प्रकार की गम्भीर कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा ।

(घ) और (ङ) कपास के निर्यात के लिए कोटों को रिलीज करते समय सरकार ने घरेलू वस्त्र उद्योग की कच्चे माल की मांग को ध्यान में रख कर ही केवल निर्यात योग्य देशी कपास को ही रिलीज किया था । इसके अतिरिक्त भारतीय कपास निगम ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम, राज्य वस्त्र निगमों, सरकारी कताई मिलों, निजी क्षेत्र की मिलों आदि जैसे प्रयोगकर्ताओं को कपास की लगभग 7.45 लाख गांठों की सप्लाई भी की । राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम (एन एच डी सी) की स्थापना मुख्यत: हथकरघा क्षेत्र को उचित कीमत पर यार्न की सप्लाई की व्यवस्था करने के उद्देश्य से की गई है ।

सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि

*235. **डा० रत्नाकर पाण्डेय** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में सोने और चांदी की कीमतों में हाल ही में वृद्धि होने के क्या कारण हैं ; और

(ख) इन बहुमूल्य धातुओं के मूल्यों में वृद्धि को रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) सोने और चांदी के मूल्यों में वृद्धि, रुपए की विनिमय दर में समायोजन, इन धातुओं की सट्टेबाजी और विवाह के मौसम में मांग बढ़ जाने जैसे कारणों से हुई हैं।

(ख) चूंकि सोना और चांदी आवश्यक वस्तुएं नहीं हैं इस प्रकार सरकार इसका मूल्य विनियमित नहीं करती है ।